बिहार सरकार

विकसित भारत - समृद्ध बिहार

बिहार राज्य के स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता

₹50 करोड़

तक की लागत वाले सिविल कार्यों में बिहार के निवासी संवेदकों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

सम्बंधित सिविल कार्यों में न्यूनतम 75% श्रमिक बिहार के निवासी होंगे

अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार

एवं बिहार के लोगों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम

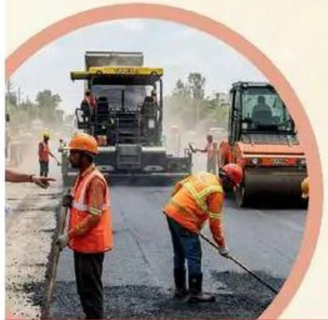

उद्देश्य

- राज्य के भीतर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करना
- स्थानीय संवेदकों की भागीदारी बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को गति देना
- विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बिहार की स्थानीय क्षमता को सशक्त करना
- निर्माण कार्यों के माध्यम से राज्य के युवाओं और श्रमिकों को अधिक अवसर उपलब्ध कराना
- सात निश्चय-3 के लक्ष्य के अनुरूप रोजगार सृजन को व्यवहारिक धरातल पर आगे बढ़ाना

स्थानीय को मौका, विकास को ताकत

PR NO - 004280 (I&PRD) D.2026-27

सम्राट सरकार के बड़े फैसले • सरकार की 'लोकल फॉर वोकल' को बढ़ावा देने की तैयारी

विदेश नहीं... बिहार घूमिए

सरकारी खर्चे पर परदेस नहीं जाएंगे मंत्री-अफसर

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहार सरकार के खर्चे पर विदेश यात्रा पर रोक लगेगी। मंत्री और अफसर सरकारी खर्चे पर दूसरे देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इधर, सरकार ने अपने अफसर-कर्मियों को सपरिवार बिहार के पर्यटन स्थलों पर घुमाने की बात तय की। उन्हें 3 महीने में एक बार शुक्रवार व शनिवार को पर्यटन स्थल पर जाना होगा। वहां रात्रि विश्राम करना होगा। सरकार तय टीए-डीए देगी। बाकी खर्चे अफसर-कर्मियों के होंगे। मंशा, ''लोकल फॉर वोकल'' को बढ़ाने की है। घूमने वाले अपना अनुभव और सुझाव बताएंगे। इसी अनुसार सुधार या इंतजाम होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, विदेश यात्रा पर रोक अगले 6 महीने तक रह सकती है। सरकारी खर्चे पर बिहार के मंत्री-अफसर विदेश जाते रहे हैं। इसको लेकर एकाध दिनों में बाकायदा आदेश जारी होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर इसका मजमून लगभग तैयार है। इसे अमेरिका-ईरान-इजराइल युद्ध को ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए पेट्रोल बचत से लेकर विदेश यात्रा तक से परहेज करने के आह्वान से जोड़कर देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री के इस आह्वान का बिहार में फौरी असर हुआ। प्रधानमंत्री ने अपना कारकेड छोटा किया, तो तत्काल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी यही किया। अपने कारकेड को सिर्फ 3 गाड़ियों तक सीमित किया। एक गाड़ी खुद के लिए, तो आगे-पीछे की 2 गाड़ियों में उनके सुरक्षाकर्मी तथा अन्य लोग। राज्यपाल ने भी ठीक यही किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री-अफसरों के आगे-पीछे घूमने वाली गाड़ियां भी कम हुईं। मुख्यमंत्री ने ''नो व्हीकल डे'' मनाने की बात कही। अफसरों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से मीटिंग करने को कहा। ''वर्क फ्रॉम होम'' पर जोर दिया। विदेश यात्रा पर पाबंदी की बात, इसी कड़ी का खास हिस्सा है।

'बिहार दर्शन'... शुक्रवार-शनिवार को पर्यटन स्थल पर कर्मियों को घुमाएगी सरकार

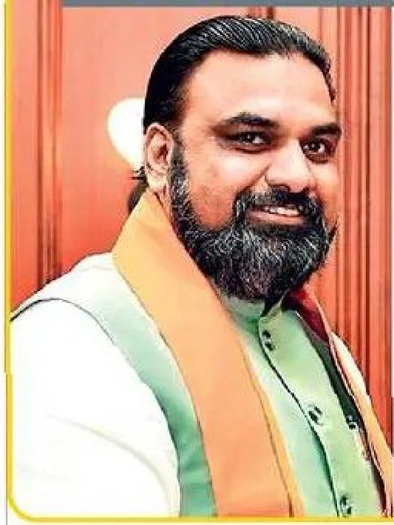

गृह जिला छोड़कर होगा 'बिहार दर्शन', 3 स्थलों का भ्रमण जरूरी

बिहार सरकार ने 'बिहार दर्शन' योजना शुरू की है। इसके तहत अफसर-कर्मी गृह जिला छोड़कर दूसरे जिलों में सपरिवार भ्रमण करेंगे। शुक्रवार और शनिवार को पर्यटन स्थल पर रुकना होगा। यात्रा के बाद फोटो, अनुभव और सुझाव का प्रतिवेदन विभाग को सौंपना अनिवार्य रहेगा।

घूमने की फोटो व जानकारी साझा करनी होगी

- गृह जिला छोड़कर दूसरे जिले में भ्रमण करना जरूरी होगा।
- शुक्रवार-शनिवार को पर्यटन स्थल पर रात्रि विश्राम करना होगा।
- अफसर-कर्मी सपरिवार बिहार दर्शन के लिए भ्रमण करेंगे।
- घूमने के दौरान फोटो और जानकारी साझा करनी होगी।
- अनुभव और सुझाव का प्रतिवेदन विभाग को देना होगा।
- होम स्टे और ईको टूरिज्म को प्राथमिकता देनी होगी।
- प्रतिवेदन जुटाने के लिए नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे।
- पर्यटन सुविधाओं की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

पर्यटन बढ़ेगा, बिहार में ही खर्च होगा पैसा

- बिहार में लोकल पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।
- पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार आसानी से हो सकेगा।
- दूसरे लोग भी घूमने आने के लिए प्रेरित होंगे।
- स्थानीय कारोबार और रोजगार को नया बढ़ावा मिलेगा।
- पर्यटन क्षेत्रों के विकास की संभावनाएं और मजबूत होंगी।
- अफसरों के सुझाव से सुविधाओं में सुधार हो सकेगा।
- होम स्टे और ईको टूरिज्म को मजबूती मिल सकेगी।
- बिहार का पैसा बिहार में ही खर्च हो सकेगा।

इधर मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की, सौर ऊर्जा का खूब प्रचार-प्रसार करने को कहा

बिहार के 10 लाख घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे : सम्राट

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहार अब अपनी बिजली खुद पैदा करने की राह पर बड़े कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम की जाएगी और सूरज की रोशनी से हर घर को जगमग किया जाएगा। सोमवार को ऊर्जा विभाग की हाई-लेवल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने 'नेक्स्ट लेवल' का विजन साझा किया। उन्होंने दो टूक कहा कि 10 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर युद्ध स्तर पर सोलर संयंत्र लगाए जाएं। वे सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीन पर उतारने के लिए रफ्तार बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जहां भी सोलर पैनल लगे हैं, उनका मेंटेनेंस हर हाल में दुरुस्त रहना चाहिए। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है-लोगों को बिजली के लिए दूसरों का मुंह न ताकना पड़े।

भास्कर एनालिसिस आत्मनिर्भरता का विकल्प जरूरी

बिहार में बिजली की मांग जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे केवल पारंपरिक कोयला आधारित बिजली से पूरा करना न तो सस्ता है और न ही पर्यावरण के अनुकूल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का 10 लाख घरों पर सोलर लगाने का दांव एक बड़ा गेम-चेंजर है। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ-साथ आत्मनिर्भरता का विकल्प भी मिलेगा। जीविका दीदियों को इस मिशन से जोड़ना एक सोची-समझी रणनीति है। वहीं, कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का मतलब है-किसानों की लागत में भारी कमी। यह योजना न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि बिहार के हर गरीब और किसान की जेब में सीधे बचत का पैसा डालेगी।

चौथी बार बढ़े पेट्रोल–डीजल के दाम, सीतारमण बोलीं– 'थ्री एफ' पर रखनी होगी सतर्क नजर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ पेट्रोल 2.61 तो डीजल 2.71 रुपये महंगा, अधिकांश शहरों में पेट्रोल 100 के पार

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत सोमवार को 100 डालर प्रति बैरल के नीचे आ गई लेकिन दूसरी तरफ घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 2.61 तो डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। 15 मई से लेकर अब तक चार बार पेट्रोल व डीजल के खुदरा दाम बढ़ाए जा चुके हैं। पेट्रोल के दाम में पिछले 10 दिनों में 7.50 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है।

देश के ज्यादातर शहरों में अब पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर हैं। इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ–साथ उर्वरक की कीमतें भी अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे समय में ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा (थ्री एफ यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर और फोरन एक्सचेंज) बचाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मुंबई से प्रेट्र के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट सिर्फ एक भू–राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि इससे आम लोगों के लिए ईंधन महंगा होगा। सरकार डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके एक लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठा रही है। मौजूदा माहौल में जब पश्चिम एशिया की जंग वैश्विक बाजारों में भूचाल ला रही है और देश में लागत बढ़ा रही है, हमें ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा बचाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पीएम नरेन्द्र मोदी के आह्वानों का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने देशवासियों से पेट्रोल–डीजल बचाने और सोने न खरीदने की अपील की थी ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके।

निर्मला सीतारमण। फाइल

बढ़ सकती है खुदरा महंगाई पेज>>5

विकसित भारत के निर्माण की राह

सीपी राधाकृष्णान

निरंतर विकास का युग बनाने के लिए सरकार और जनता, दोनों का साझा उत्साह ही देश की प्रगति का कारण है

जब मैं तिरुप्पुर के स्कूल में पढ़ता था, तब मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठते थे कि भारत अपनी महानता कब वापस पाएगा? हमारे गरीब और वंचित भाई बहनों को सम्मानजनक जीवन कब मिलेगा? मुझे खुशी है कि किशोरावस्था में मेरे मन में जो विचार थे, वे अब साकार हो रहे हैं। मैं अक्सर खुद को स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों की याद दिलाता था, 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको।' स्वामीजी के ये उद्गार हर व्यक्ति में देशभक्ति और समर्पण की भावना जगाने की अपार शक्ति रखते हैं। मेरा हमेशा यह विश्वास रहा कि जब भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा, तब वह पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र बनकर उभरेगा। अब हमें अपनी आंखों के सामने तिरुवल्लुवर के इन शब्दों की सच्चाई देखने का अवसर मिल रहा है- 'जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं, वे ठीक वही हासिल करते हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है।' पिछले एक दशक में मुझे यह देखकर खुशी होती है कि हमारा देश जबरदस्त ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

आज जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और तेजी से आगे बढ़ रही है। इस दौर को निरंतर विकास का युग बनाने के लिए सरकार और जनता दोनों का साझा उत्साह ही इस प्रगति का कारण है। एक समय कमजोर अर्थव्यवस्था माने जाने वाला हमारा देश आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी बड़ी आर्थिकी बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारा आर्थिक विकास समावेशी रहा है। पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ भारतवासी अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हुए हैं। अब तक भारत में गरीब और बेघर लोगों के लिए लगभग चार करोड़ पक्के घर बनाए जा चुके हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को पाइप से पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है, जिस पर 2.3 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है। मैंने गांवों में लोगों को इलाज की सुविधा न मिलने के कारण परेशान होते देखा है। उनके परिवारों की पीड़ा देखकर मुझे दुख होता था। आज देश इस संकल्प के साथ आयुष्मान भारत योजना चला रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचें। इसी का परिणाम है कि अब 44 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है। केवल पिछले एक वर्ष में ही 2.5 करोड़ लोगों ने इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज प्राप्त किया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। तीन करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी बनकर अपना जीवन संवार चुकी हैं। महिलाओं के दैनिक जीवन को आसान बनाने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए लगभग दो करोड़ नए एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में आधी आबादी की भागीदारी को और सशक्त बनाएगा।

अवधेश राजपूत

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं तथा एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों ने क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बहुत लाभ पहुंचाया है। युवा शक्ति के लिए पिछले दस वर्षों में ही 13 नए आइआइटी स्थापित किए गए हैं। आइआइएम की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। एम्स की संख्या सात से बढ़कर 23 हो चुकी है। मेडिकल कालेजों की संख्या भी बढ़कर 823 हो गई है। यह गर्व की बात है कि मेडिकल छात्रों के लिए सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,29,603 हो गई है। हम विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे का लगभग 99 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। हवाई अड्डों की संख्या भी 74 से बढ़कर 163 हो गई है और उड़ान योजना के तहत आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई है। नए पंबन ब्रिज से लेकर चिनाब ब्रिज हो या बोगीबील पुल, भारत अब आधुनिक बुनियादी ढांचे के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी भारत के अंतिम गांव माने जाते थे, वे अब देश के प्रथम गांव बन चुके हैं और वाइब्रेंट विलेज स्कीम के माध्यम से उनका विकास किया जा रहा है।

चंद्रयान-3 की सफल लांचिंग ने भारत को उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान के नए युग में पहुंचा दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ के क्षेत्र में वैश्विक कंपनियां भारत को अपना केंद्र बना रही हैं, जिससे निवेश में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत अब सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक माडल बनकर उभर रहा है। मोबाइल फोन उत्पादन में भी हमने विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है। जो भारत कभी मोबाइल फोन आयात करता था, वही आज 300 करोड़ डालर के मोबाइल फोन निर्यात करने वाला देश बन चुका है। ये सभी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव बनेंगी। कई दशकों तक देश ने केवल आतंकवाद ही नहीं, बल्कि उग्रवाद और वामपंथी चरमपंथ जैसी चुनौतियों का भी सामना किया है।

हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक यानी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक, भारत एक अग्रणी वैश्विक शक्ति बने और दुनिया का मार्गदर्शन करने की स्थिति में पहुंचे। कठिन परिश्रम का यह दौर ही अमृतकाल है। जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में आजादी की प्यास थी, उसी तरह आज के युवाओं के मन में राष्ट्र विकास का संकल्प होना चाहिए। इस अमृतकाल में यदि युवाओं के विचार और प्रयास देशभक्ति, उच्च आदर्शों और श्रेष्ठ चरित्र के साथ आगे बढ़ेंगे, तब हम 2047 में एक विकसित भारत का सपना साकार होते देख सकेंगे।

(लेखक भारत के उपराष्ट्रपति हैं)
response@jagran.com

SC blames NTA for repeated NEET question paper leaks

Two-judge Bench issues notice to the Union Ministry of Education, NTA, and others on pleas to 'replace or fundamentally restructure' the exam body and make it answerable to Parliament

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Monday squarely blamed the National Testing Agency (NTA) for the National Eligibility-cum-Entrance Test-Undergraduate (NEET-UG), 2026, paper leak, saying the exam body sadly had not learnt its lesson even two years after the previous security breach in 2024.

The hard work of 23 lakh students came to nothing with the cancellation of the examination after it was learnt that the question paper had been leaked.

A Central Bureau of Investigation (CBI) probe is under way into the issue and a retest is scheduled on June 21.

"It is so sad, really, that the NTA has not learnt its lesson. We had with such difficulty heard the petitions in 2024 and passed orders... We had directed the constitution of a committee to give recommendations... Those recommendations, we believe, were accepted... a monitoring/high-powered committee was appointed," Justice P.S. Narasimha, heading a two-judge Bench, observed on Monday while hearing a petition filed by the Federation of All India Medical Association to "replace or fundamentally restructure" the NTA.

> It is so sad, really, that the NTA has not learnt its lesson. We had with such difficulty heard the petitions in 2024 and passed orders... We had directed the constitution of a committee to give recommendations... Those recommendations, we believe, were accepted
>
> **JUSTICE P.S. NARASIMHA**
> Supreme Court judge

Affidavit sought

The Bench directed the NTA to file an affidavit in the next three days on measures taken by it implement the recommendations of the monitoring/high-powered committee and listed the case for hearing on an urgent basis later this week.

The top court also issued notices to the Union of India, the Union Ministry of Education, and other respondents arraigned by the petitioners.

CONTINUED ON
» PAGE 10

Pradhan seeks report on CBSE marking glitches

NEW DELHI
Union Minister for Education Dharmendra Pradhan has sought a detailed report on the glitches in the CBSE portal after multiple complaints about the new On Screen Marking system. » PAGE 12

Finance Commission transfers and equity issue

The Finance Commission (FC), constituted under the Constitution, determines the distribution of the Union's gross tax revenues between Centre and States and among the States themselves to address vertical and horizontal fiscal imbalances. Following earlier commissions, the 16th FC has retained the vertical devolution share of 41% for the States and continued to emphasise equity as the guiding principle in determining horizontal transfers.

During consultations with the FC, States raised several concerns regarding the structure of fiscal transfers. Since cesses and surcharges exceeded 15% of gross tax revenues, they should either be included in the divisible pool or capped at around 8%-10%. In addition, the Centre receives substantial non-tax revenues from natural resource extraction, asset monetisation and surplus transfers from the Reserve Bank of India.

States and pressures

States also face mounting fiscal pressures. The COVID-19 pandemic, structural changes introduced by the Goods and Services Tax (and recent rate rationalisation from four rates to two principal rates), and mounting public debt further constrained their fiscal space. Moreover, the growing dominance of Centrally Sponsored Schemes has narrowed their fiscal autonomy (the restructuring of the National Rural Employment Guarantee programme requires States to bear 40% of programme costs), while buoyancy of central taxes has slowed. These factors could reduce the actual transfers to States, leading several States to demand a 50% vertical share.

Another concern is frequent changes in devolution criteria and their assigned weights across successive FCs in order to transfer more resources to fiscally weaker States, making it difficult for States to predict their future shares. Many States called for a reduced weight for the income-distance criterion and suggested adjusting it for purchasing-power differences to better reflect variations in the cost of living.

Over time, the shares of better-performing States have steadily declined compared with those of major beneficiary States. The combined shares of four major beneficiary States – Bihar (including Jharkhand), Madhya Pradesh (including Chhattisgarh), Uttar Pradesh (including Uttarakhand) and West Bengal – increased from 42.5% during the Sixth FC period to 51% under the 15th FC. In contrast, the combined share of the four southern States – Andhra Pradesh (including Telangana), Karnataka, Kerala and Tamil Nadu – declined from 24.8% to 15.8%, widening the gap to 35.2%. Continued reliance on unconditional equalisation transfers may weaken incentives for revenue mobilisation and fiscal discipline in weaker States. Moreover, rising transfers to poorer States have not eliminated disparities in public expenditure even on basic services. In 2022-23, Bihar spent ₹937 per person on health, against Arunachal Pradesh's ₹10,148 (10.8 times lower), while Bihar's per-student spending on elementary education in 2023-24 was ₹20,282 compared with Sikkim's ₹1,30,498. These gaps show that fiscal transfers alone have not ensured convergence in public service delivery.

K.R. Shanmugam

Former Director, Madras School of Economics, and Consultant to the Government of Tamil Nadu

Under the 16th Finance Commission, arbitrary weights affect better-performing States

Recommendations of Finance Commission

The 16th FC accepted the Centre's argument that cesses and surcharges cannot be shared because they often finance welfare and infrastructure programmes that indirectly benefit States and retained 41% vertical share. It also abolished revenue-deficit grants as well as sector-specific and State-specific grants and recommended that States discontinue off-budget borrowings, bring all liabilities onto their budgets and maintain fiscal deficits below 3%. These measures could increase short-term fiscal stress for States.

The FC made only modest adjustments to the criteria used by the 15th FC. Income distance received a weight of 42.5%; population 17.5%; area 10%; forest cover 10%; and the demographic criterion – modified by replacing the inverse fertility rate with population growth – 10%. It also introduced States' contribution to national GDP, replacing tax effort, with a 10% weight. However, instead of using actual GSDP shares, the FC applied a square-root transformation to State GSDP shares, with a weight of just 10%, far below the expected 25%. This significantly reduced the advantage of economically stronger States and altered the rankings. Maharashtra's actual GSDP share of 14.23% fell to 8.31% after the transformation, while Tamil Nadu's declined from 9.09% to 6.67% and Karnataka's from 8.95% to 6.59%. At the same time, the shares of many smaller States increased.

Consequently, overall devolution shares of 14 States rose marginally compared with the 15th FC. Karnataka gained the most (0.484 percentage point increase), followed by Kerala (0.457) and Gujarat (0.277). Tamil Nadu saw only a negligible rise, from 4.079% to 4.097%. Meanwhile, the shares of 14 States declined, with Madhya Pradesh experiencing the largest reduction (0.503 percentage points), followed by Arunachal Pradesh (0.403) and Uttar Pradesh (0.32).

From a longer-term perspective, however, disparities remain substantial. Under the 16th FC, the southern States' share has risen slightly to about 17%, while the share of the largest beneficiary States has fallen to just under 50% – a shift of only about 1.2% in favour of the southern States. The balance between equity and efficiency has changed only marginally. Under the 15th FC, efficiency-related criteria accounted for 25% of the weight and equity criteria for 75%; under the 16th FC, this has shifted to 30% and 70%, respectively – an adjustment too small to significantly alter outcomes. Poorer States such as Uttar Pradesh (17.62%), Bihar (9.95%), Madhya Pradesh (7.35%) and West Bengal (7.22%) continue to receive larger shares than fiscally stronger and better-performing States.

Devolutions with alternative schemes

Alternative weighting schemes suggest that the outcomes could have been different. If the FC had assigned a 25% weight to the square root of GDP contribution while reducing the weight of income distance to 27.5%, Karnataka's share would have increased from 4.131% to 4.928%, Maharashtra's from 6.441% to 7.218%, and Tamil Nadu's from 4.097% to 4.867%. Under an equal-weight scheme across the six criteria, their shares would have risen further to 5.544%, 7.845%, and 5.246%, respectively.

Had the FC used actual GSDP share (instead of square root formula) with 10% weight, the devolution shares of Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu would have increased to 7.033%, 4.367% and 4.342% respectively. With 25% weight (and 27.5% weight to income distance), they would have increased to 8.698%, 5.517% and 5.478%. With equal weighting scheme, their respective shares might have increased to 8.833%, 5.937% and 5.653%. That is, their respective shares increased by 2.392%, 1.806% and 1.556%.

Given that the 16th FC estimates total vertical transfers of ₹104 lakh crore over the award period, these differences are significant. A 2.392% increase in Maharashtra's share would translate into an additional ₹2.49 lakh crore, or about ₹49,744 crore annually. Karnataka's additional 1.806% share would yield about ₹1.88 lakh crore, or roughly ₹37,565 crore annually. Tamil Nadu's 1.556% increase would amount to approximately ₹1.62 lakh crore, or ₹32,365 crore annually.

In India, unlike other large federations such as Australia and China, States with greater political influence in terms of parliamentary representation are not necessarily the economically stronger ones. Consequently, these States tend to receive higher fiscal transfers. The issue is likely to intensify after delimitation, as governments may have stronger incentives to favour politically influential States. Since the FC's primary objective is to address both vertical and horizontal fiscal imbalances, future FCs should place greater emphasis on fiscal capacity and fiscal outcome indicators rather than relying predominantly on non-fiscal indicators. Additionally, they should adopt more data-driven approaches for assigning weights, such as the principal component analysis method.

The views expressed are personal

Indian mobile market hit as global semicon industry faces 'severe memflation'

India sees shortage of sub ₹10,000-₹15,000 phones as leading chips manufacturers divert capacities to meet humongous demand for high-bandwidth memory required to support AI infra

Mini Tejaswi
BENGALURU

The semiconductor industry globally is experiencing a severe structural 'memflation' (inflation caused by memory chips shortage), with skyrocketing prices leading to huge disruptions in price sensitive consumer electronics and mobile phone markets in India, said industry experts.

The key reason is that global wafer and advanced packaging capacities are increasingly being allocated toward high bandwidth memory (HBM) and AI infrastructure due to significantly higher demand and margins. A typical HBM takes 2-3x wafer capacity compared with a conventional DRAM.

This is making availability of conventional DRAM and NAND used in mainstream electronics tighter, according to India Electronics & Semiconductor Association (IESA).

Dynamic Random-Access Memory, or DRAM, is a type of computer memory used in PCs, laptops, and smartphones to temporarily store data that the processor needs to actively use. While NAND is a type of memory storage used in smartphones that retains data even without power.

Industry experts also confirmed that there is a shortage of sub ₹10,000 to ₹15,000 phones across the country as leading semiconductor (memory chips) manufacturers are diverting all their energies and production capacities away from standard consumer chips to meet the humongous demand for high-bandwidth memory required to support AI infrastructure.

Off reach: The entry-level smartphone segment is under severe pressure due to rising memory chip costs. B. JOTHI RAMALINGAM

India very vulnerable

B.V. Naidu, a foundational architect in India's semiconductor and Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) ecosystem and a former president of IESA, India is extremely vulnerable to memory chip shortage due to its heavy reliance on electronic component imports and a consumer base driven by price elasticity.

"It seems global chip makers are prioritising premium brands such as Apple and Samsung for standard memory allocation, leaving budget brands in India and in other geographies to starve of chip/component supply. This has resulted in a short supply of economy smartphones in India. Also, I was told prices of several brands of cellphones have gone up by at least 15-20%," Mr. Naidu said.

As per IESA, higher DRAM and NAND prices, combined with the shift to AI-enabled applications and larger storage needs, are making the sub ₹10,000 to ₹15,000 category increasingly difficult to sustain profitably.

"The market is witnessing a structural recalibration toward higher-value devices. That means, phone makers are prioritising premium phone production over entry level phones," explained Ashok Chandak, president, IESA.

Confirming the trend, Rajeev Rajput, Senior Principal Analyst at Gartner, in a recent report said, "Memflation will destroy, or at least delay, non-AI demand into 2028, to varying degrees depending on the application. Technology suppliers should prepare for higher prices during the first half of 2026, followed by persistent but moderating price increases throughout the rest of the year." CIOs and IT leaders should be cautious about signing supply agreements with unfavourable pricing terms that extend beyond 2027, he warned.

Echoing a similar sentiment, Mr. Chandak said while capacity expansion announcements were underway globally, meaningful and substantial relief may take up to another two years because semiconductor capacity creation was highly capital-intensive and time-consuming.

"We expect the market to remain tight through 2026-2027, with gradual normalisation thereafter," he added.

On bill of materials (BOM) pressure and smartphone profitability, Mr. Chandak observed, memory pricing has become one of the biggest cost pressures in smartphone and entry level laptop manufacturing.

Iran says progress on several issues, but agreement with U.S. not yet close

Tehran talks down hopes of imminent peace deal with U.S.; Iran official says 'conclusion reached on a large portion of the issues under discussion'; Iranian state media reports officials on a visit to Qatar as part of 'diplomatic process' to end war

Agence France-Presse
TEHRAN

Iran warned on Monday that, while some progress had been made, it was not yet close to striking a deal with the United States to end the war in West Asia, after a weekend of mixed messages from Washington and Tehran.

World oil prices tumbled on renewed optimism about an agreement, after top U.S. diplomat Marco Rubio suggested a deal could be reached within the day but a top Iranian official responded: "No one can make such a claim."

Beneath the calm: Vessels sailing through the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, on Monday. REUTERS

"We thought we might have some news last night, maybe today," U.S. Secretary of State Rubio told reporters during a visit to New Delhi, referring to hopes for a deal.

But in Tehran, Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baqaei poured cold water on hopes for a quick final settlement.

"It is correct to say that we have reached a conclusion on a large portion of the issues under discussion," he told a weekly news briefing. "But to say that this means the signing of an agreement is imminent – no one can make such a claim."

Service fees in Hormuz

Mr. Baqaei stressed that Iran would continue to manage maritime traffic through the Strait of Hormuz by charging service fees. "The services that are provided – navigational services in addition to the measures necessary to protect the environment of the Strait of Hormuz, the Persian Gulf and the Sea of Oman – require the collection of certain fees," he said.

Earlier, U.S. President Donald Trump had said that he had told his negotiators "not to rush into a deal, in that time is on our side", and warned that the U.S. naval blockade would remain in place until a deal was reached.

Meanwhile, Iran's top negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf arrived in Qatar on Monday, state media reported. A delegation headed by "Mr. Ghalibaf, travelled to Doha today. This trip comes as part of the diplomatic process", said the official IRNA news agency, adding that talks will be held to end the war.